**एअर इंडिया द्वारा फ्रांस व अमेरिका से 470 विमानों की खरीद के समझौते नागरिक विमानन के क्षेत्र में भारत की एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने के संकेत तो हैं ही, कोविड व रूस-यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में ये सौदे रोजगार बढ़ाने के साथ यूरोप-अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते की मजबूती के बारे में भी बताते हैं।**

## नई ऊंचाइयों पर

टाटा समूह की कंपनी एअर इंडिया द्वारा फ्रांस की कंपनी एअरबस से 250 और अमेरिकी कंपनी बोइंग से 220 विमानों की खरीद के समझौते नागरिक विमानन के क्षेत्र में भारत की एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने के स्वागतयोग्य संकेत तो हैं ही, इनसे फ्रांस और अमेरिका के अलावा ब्रिटेन के साथ भी भारत के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि एअरबस में रॉल्स रॉयस (ब्रिटिश कंपनी) का इंजन लगता है। कुल 470 विमानों की खरीद का यह सौदा एअर इंडिया और भारतीय विमानन क्षेत्र का ही सबसे बड़ा सौदा नहीं है, बल्कि 2011 में अमेरिकन एअरलाइंस द्वारा 460 विमानों की खरीद को ध्यान में रखते हुए इसे विमानन इतिहास का भी सबसे बड़ा सौदा बताया जा रहा है। कुल 470 विमानों में से पहला विमान इस साल के अंत तक देश में आने, जबकि शेष विमानों के वर्ष 2025 के मध्य तक पहुंचने की उम्मीद है। इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विमानन क्षेत्र में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने जा रहा है। गौरतलब है कि भारत के बढ़ते विमानन क्षेत्र को आगामी 15 साल में 2,000 से अधिक विमानों की जरूरत पड़ने वाली है। बोइंग सौदे के संदर्भ में बाइडन से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जहां भारत-अमेरिका के मजबूत संबंधों के बारे में बताया, वहीं बाइडन का कहना था कि इस सौदे से अमेरिका में 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का भी यही कहना था कि इससे रॉल्स रॉयस में रोजगार बढ़ेगा। एअर इंडिया के इस खरीद सौदे से जहां इंडिगो को कड़ी चुनौती मिलने वाली है, जिसका घरेलू विमानन क्षेत्र के 50 फीसदी से ज्यादा हिस्से पर कब्जा है, वहीं इससे एअर इंडिया को उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। सिर्फ यही नहीं कि जनवरी,



2022 में घाटे में चलने वाली एअर इंडिया को टाटा समूह द्वारा खरीदने के बाद इसमें जान फूंकने का यह विराट और महत्वाकांक्षी प्रयास है, बल्कि कोविड और रूस-यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में विमानों की खरीद के ये सौदे इन चारों देशों में रोजगार बढ़ाने के साथ अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में भी मददगार साबित होंगे।

# कल्याणकारी योजनाओं से बदली सियासत

**नियम-आधारित, प्रत्यक्ष हस्तांतरण और जेम (जन धन बैंक खाते, आधार बायोमेट्रिक पहचान और मोबाइल फोन) के उपयोग पर जोर देने के साथ 'नए कल्याणवाद' ने सत्ताधारी दलों के लिए वोट और राजनीतिक समर्थन हासिल किया है। क्या इसका कल्याणकारी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन से कोई संबंध है?**



शिखर सिंह

पिछले एक दशक में भारत में वितरण को अधिक कुशल बनाने के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों का एक विशेष दृष्टि से प्रसार किया गया है। इसका अनिवार्य रूप से अर्थ यह है कि राजनेता प्रौद्योगिकी से लैस समाधानों के जरिये अंतिम कड़ी तक वितरण को बेहतर बनाना चाहते हैं, जिससे रिसाव, विशेषाधिकार और पक्षपात कम हो सके। *द इकोनॉमिस्ट* ने आकलन किया कि इस 'उच्च प्रौद्योगिकी कल्याण सुरक्षा कवच' में करीब तीन सौ योजनाएं शामिल हैं, जिन्होंने 95 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया है, जिनमें अधिकांश गरीब शामिल हैं और यह सरकारी खर्च में जीडीपी के तीन फीसदी के बराबर है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि नियम-आधारित, प्रत्यक्ष हस्तांतरण और जेम (जन धन बैंक खाते, आधार बायोमेट्रिक पहचान और मोबाइल फोन) के उपयोग पर जोर देने के साथ इस 'नए कल्याणवाद' ने सत्ताधारी दलों के लिए वोट और राजनीतिक समर्थन हासिल किया है।

लेकिन क्या दक्ष कल्याणवाद अपने साथ वह राजनीतिक लाभांश लेकर आता है, जैसा अनेक लोग मानते हैं कि यह करता है? कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रभाव आपस में जुड़े दो प्रश्नों पर टिका है : क्या मतदाता वितरण लाभ के लिए राजनेताओं को पुरस्कृत करते हैं? और क्या मतदाता प्रक्रिया की परवाह करते हैं, मसलन ये लाभ उन तक कैसे पहुंचे? दूसरे शब्दों में क्या मतदाता भ्रष्टाचार और भेदभाव में कमी लाने वाले कुशल क्रियान्वयन को पुरस्कृत करते हैं?

शासन संबंधी सुधार अक्सर विशेषाधिकार और भेदभाव को कम कर चोरी या भ्रष्टाचार में कमी करते हैं। ऐसे प्रयासों के पीछे भ्रष्टाचार का सार्वजनिक तिरस्कार होता है। फिर भी, हमारे अनुभव बताते हैं कि परिवार, रिश्तेदारों, या सहजातीय लोगों को पक्षपात की व्यापक उम्मीदें होती हैं, तो दूसरी ओर कभी-कभी सरकारी संपत्ति की चोरी भी होती है।

जहां तक बाद वाली बात है, तो इसका एक विनोदी चित्रण *कटियाबाज* फिल्म में दिखाया गया है। और पहली बात, हमारी जाति आधारित राजनीति में असंदिग्ध रूप से मौजूद है। शोध के सिलसिले में मेरे दो साल के जमीनी कार्य के दौरान पत्रकारों, राजनेताओं और सामान्य मतदाताओं ने अपेक्षाओं के बारे में लगभग समान रूप से यही कहा, 'हमारा है, हमारे लिए करेगा।' एक राजनेता ने कहा, 'जाति स्वार्थ से जुड़ी है।'

तो फिर, मतदाता जातीय, राजनीतिक, या भौगोलिक रेखाओं के साथ कुशल कार्यान्वयन और पक्षपात के बीच संतुलन में कहां पर खड़े हैं? शोध के सबूतों के आधार पर मेरा तर्क है कि भारत में मतदाता अच्छे प्रदर्शन को पुरस्कृत करते हैं, वे कुशल कार्यान्वयन की तुलना में परिणामों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। मतदाता दक्षता को मामूली तवज्जो देते हैं। हमारे समाचार पत्रों में चित्रित तस्वीर से दूर, शासन सुधार (विशेष रूप से बेहतर कार्यान्वयन) के लिए मतदाताओं की भूख सीमित लगती है।

**वितरक नीति से जुड़े प्रयोग :** इनसे जुड़े प्रश्नों के जवाब तलाशने के लिए मैंने एक ऑनलाइन सर्वे (1,047 मतदाता) और सी-वोटर इंडिया द्वारा 12 विभिन्न भाषाओं में किए गए एक राष्ट्रीय प्रतिनिधिक टेलीफोन सर्वे (5,350 मतदाता) का इस्तेमाल किया।

प्रत्येक सर्वेक्षण के भीतर मतदाताओं को औचक रूप से मौजूदा सरकार पर नकारात्मक प्रदर्शन की जानकारी, उसके किसी एक कल्याणकारी कार्यक्रम के बारे में सकारात्मक जानकारी, या भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर जोर देने वाले किसी कल्याणकारी कार्यक्रम के बारे में सकारात्मक जानकारी पढ़ने के लिए कहा गया। नकारात्मक स्थिति के रूप में ऐतिहासिक बेरोजगारी, ईंधन मुद्रास्फीति और बढ़ती आय असमानता की ओर इशारा करते हुए कहा गया कि 'भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं कर रही है।' वहीं सकारात्मक स्थिति के रूप में कल्याणकारी कार्यक्रम (उज्ज्वला या पीएम आवास योजना) से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या सामने आई। और दक्षता के रूप में सुधार के लिए फर्जी दावे (बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण), भ्रष्टाचार और विशेषाधिकार (बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, संपत्ति की जियोटैगिंग आदि) को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विशिष्ट कदमों का उल्लेख किया गया।

मतदाताओं ने नतीजों को कहीं अधिक तवज्जो दी, बजाय क्रियान्वयन को। मैंने पाया कि मतदाताओं का रुख सकारात्मक प्रदर्शन से संबंधित जानकारी की ओर होता है। मतदाताओं को जब ऐतिहासिक बेरोजगारी, बढ़ती असमानता और महंगे ईंधन के बारे में विचार करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने मोदी सरकार को दस में से छह अंक दिए। कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में बताए जाने के बाद उन्होंने सरकार का अधिक अनुकूल मूल्यांकन किया (10 में से 7 से अधिक)। इस तरह देख सकते हैं कि कैसे सरकार की रेटिंग 1.14 अंक या 11 फीसदी बढ़ गई। इस विश्लेषण का नतीजा यह है कि यदि मतदाता प्रक्रिया (अर्थात लोगों को लाभ कैसे पहुंचाया जाता है) को काफी हद तक महत्व देते हैं, तो रिसाव, विशेषाधिकार और पक्षपात को कम करने के उद्देश्य से बहुत सारे शासन सुधार राजनीतिक रूप से व्यवहार्य होंगे।

वर्तमान में, भ्रष्टाचार पर सार्वजनिक विमर्श हाई प्रोफाइल मामलों तक सीमित है और भ्रष्टाचार या भाई-भतीजावाद में शामिल प्रभावशाली व्यक्तियों पर केंद्रित है। इस विमर्श के विस्तार की जरूरत है। नीति निर्माण और अंतिम छोर तक वितरण पर ध्यान केंद्रित करने वाले दाताओं और विशेषज्ञों को गुणात्मक रूप से आकलन करने की आवश्यकता है कि नागरिक दक्षता बढ़ाने वाले उपायों को कैसे देखते हैं और क्या वे उनमें कोई मूल्य देखते हैं। सार्वजनिक सूचना और जागरूकता अभियानों को पक्षपात और भ्रष्टाचार के घातक प्रभावों को अधिक स्पष्ट रूप से उजागर करने और कुशल कार्यान्वयन से होने वाले लाभ को रेखांकित करने की आवश्यकता है।

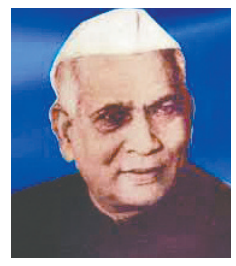

*-लेखक सीएएसआई के रिसर्च फेलो हैं।*

edit@amarujala.com

## आजादी के अमृत कथन



अलगू राय शास्त्री (1900-1967)

यदि हम सचमुच सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, तो उनकी भर्ती के समय हमें उचित ध्यान देना चाहिए और ट्रेनिंग के समय उन्हें उच्च आदर्श के व्याख्यान देने की जरूरत है।

## राज धन है मधु और राज कर्मचारी मक्खी

**यह** विधेयक (भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 1957) तो देखने में ऐसा साधारण मालूम होता है कि इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। यह पहले ही स्वीकार हो चुका है, तब इसमें केवल एक सीमा निर्धारित थी और अब इसे एक शाश्वत स्वरूप दिया जा रहा है। यह सिद्धांत तो प्राचीन काल से स्वीकार किया हुआ है कि जो राज धन है, वह मधु के समान है और राज कर्मचारी मक्खी के समान हैं, जो यदि सावधानी न बरती जाए, तो उस मधु को चाट जाएंगे। कौटिल्य ने प्राचीन काल में इसका अनुभव किया था और उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में इस संबंध में नीति प्रतिपादित की थी। हमारे कर्मचारियों के ऊपर जो दायित्व होता है, उसमें उन्हें हजारों आदमियों से डील करना पड़ता है। कभी-कभी उनके साथ कर्मचारियों का बर्ताव ऐसा लगता है, जैसे कि एक नया जूता पहना जाए, तो पहले वह पांव को चुभता है। कर्मचारियों के पास जो संपत्ति है, यदि वह उनकी स्वाभाविक आय से अधिक एकत्र हो गई है, तो किसी व्यक्ति के शिकायत करने पर उसके बारे में जांच करने का प्रश्न उठाने का अवसर मिल सकता है। तो जब छोटी-मोटी शिकायत को लेकर उनके बारे में जांच-पड़ताल करने का काम शुरू होता है, तो उसमें कर्मचारियों का बड़ा उत्पीड़न होता है। इसमें शक नहीं कि हो सकता है शिकायतें छोटी-मोटी हों, लेकिन उनका महत्व बड़ा हो।

**कितने ही सख्त कानून क्यों न आप बना दीजिए, लेकिन एक तरफ ऐसा विधेयक आएगा और दूसरी तरफ करप्शन की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार शब्द ने भ्रष्टाचार को और बढ़ाया है।**

मैं समझता हूं कि कितने ही सख्त कानून क्यों न आप बना दीजिए, लेकिन एक ओर ऐसा विधेयक आएगा और दूसरी ओर करप्शन की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार शब्द ने भ्रष्टाचार को और बढ़ाया है। यदि हम सरकारी कर्मचारियों के सिर के ऊपर इस तरह की तलवार लटका दें कि जांच होगी, तो इस बात पर हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि थोड़ी-सी गलती पर किसी को सख्त सजा न मिल जाए, इस बात की ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा। हमारी सरकार जनता की सरकार है, जनता को किसी प्रकार का कष्ट हो, तो सरकार को कष्ट होगा और अगर उसके कर्मचारियों द्वारा यह कष्ट पहुंचाया जाए, तो अवश्यमेव सरकार को ज्यादा कष्ट होना चाहिए। जहां पर सच्चा अपराधी मिल जाए और उसके विरुद्ध प्रथम दृष्टया केस साबित हो जाए, वहां उसे अवश्य दंडित किया जाना चाहिए। यदि हम सचमुच सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, तो उनकी भर्ती के समय हमें उचित ध्यान देना चाहिए और ट्रेनिंग देते समय उनके सम्मुख उच्च आदर्श के व्याख्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही, जनता की आय के अनुसार ही उनकी तनख्वाह भी बढ़ाया जाना चाहिए।

इस विधेयक द्वारा जहां हम सरकारी कर्मचारियों को जनता की सेवा करने का अवसर देते हैं, वहीं उनके हाथों में ऐसी शक्ति भी देते हैं, जिसके द्वारा उनके अंदर लालच पैदा हो सकता है। तब उसके निरोध की व्यवस्था करनी होगी और निरोध की व्यवस्था हम कर सकते हैं, उसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। हमारे देश में प्रजातंत्र है और जिस तरह की चीज हमारे जनसाधारण में है, छोटी-मोटी शिकायत कर देने की, एक झूठा चालान कर दिया किसी आदमी का और इस तरह से हम दलबंदी में पड़ जाते हैं, ऐसे लोगों के प्रति हमें बहुत सावधानी बरतनी है। अंत में मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

*-स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता अलगू राय शास्त्री के 21 मार्च, 1957 को राज्यसभा में दिए भाषण के संपादित अंश।*

## दूसरा पहलू

रिश्ता खत्म हो जाने के बाद दो पूर्व प्रेमियों ने इस म्यूजियम की शुरुआत की, जो आज क्रोएशिया में पर्यटकों के लिए सबसे व्यस्त जगह है।

## दिल टूट जाने पर इस म्यूजियम में रखी जाती हैं स्मृतियां

**बीस** साल पहले जब क्रोएशिया के दो प्रेमी जोड़े ओलिंका विस्टिसा और ड्रेजन ग्रिबिसिक के रिश्ते खत्म हुए, तो उन्होंने अपने सामान, यानी एक टीवी, कंप्यूटर और छुट्टियां बिताने के दौरान मिले स्मृतिचिह्न दो हिस्से में बांटने शुरू किए। फिर बॉनी यानी उनके पसंदीदा खिलौने की बारी आई। जब वे साथ रहते थे और ड्रेजन शाम को घर लौटते थे, तो ओलिंका बॉनी टॉय को दरवाजे पर उसका स्वागत करने के लिए खड़ा कर देती थी। छुट्टियों में बाहर जाने पर वे बॉनी के साथ फोटो खिंचाते थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि कभी अलग होंगे और बॉनी उनमें से किसी एक के पास रहेगा।



एलेक्स मार्शल

'यह म्यूजियम दुनिया भर के विफल प्रेमियों को याद दिलाता है कि उनका प्रेम कहीं न कहीं बचा हुआ है', इसके संचालकों में से एक ओलिंका कहती हैं।

अलग होने के समय उन्होंने एक अनूठी योजना पर काम शुरू किया। उन्होंने एक ऐसा म्यूजियम बनाया, जहां रिश्ते टूटने के बाद लोग अपनी चीजें यादगार के तौर पर रख सकें। इसके पीछे विचार यह था कि लोग अपने विफल रोमांस से न टूटकर जीवन में आगे बढ़ सकें। 'ऐसा एक म्यूजियम उन विफल प्रेमियों को यह भी याद दिलाता है कि उनका प्रेम कहीं न कहीं बचा हुआ है', ओलिंका कहती हैं।



इस म्यूजियम में प्रदर्शित की जाने वाली चीजों की संख्या बढ़कर 4,000 से अधिक हो गई हैं और यहां जाने का अनुभव निश्चित रूप से यादगार है।

आज ये दोनों पूर्व प्रेमी इस म्यूजियम का बखूबी संचालन करते हैं, जो क्रोएशिया में पर्यटकों के लिए सबसे व्यस्त जगह है और जो क्रोएशिया के पुराने शहर तथा राजधानी जैगरेब में एक पूर्व महल में है। दुनिया भर के पूर्व प्रेमी इसमें सिर्फ अतीत की यादगार सामान ही नहीं, चिट्ठियां और ई-मेल्स भी भेजते हैं।

इस म्यूजियम में जाने का अनुभव भी निश्चित रूप से यादगार है। मसलन, इसमें रखे गए सफेद जूते की जोड़ी के साथ एक नोट चिपका है, 'उसने अपना पसंदीदा रंग मुझ पर थोपा।' ऐसे ही एक महिला ने म्यूजियम को पैराशूट उपहार में दिया है, क्योंकि उनके प्रेमी की स्काई डाइविंग के दौरान दुर्घटना में मौत हो गई थी।

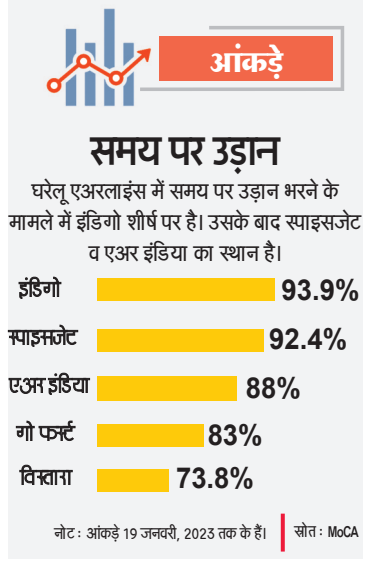

वर्ष 2006 में ओलिंका विस्टिसा और ड्रेजन ग्रिबिसिक ने टूटे दिलों के अजायबघर को अस्थायी रूप में प्रदर्शित किया था। लेकिन उसके बाद उनके पास इसे स्थायी रूप से चलाने के लिए फोन कॉल्स और ई-मेल्स के जरिये लगातार अनुरोध आने लगे, तो 2010 में उन्होंने इसे स्थायी रूप दिया। इस म्यूजियम में प्रदर्शित की जाने वाली चीजों की संख्या बढ़कर 4,000 से अधिक हो गई हैं। इस म्यूजियम की क्यूरेटर शैर्लोट फ्यूएंटीज कहती हैं, 'हाल ही में एक महिला ने 37 साल पहले हुई अपनी शादी के केक का एक टुकड़ा भेजा, जिसे मैंने फ्रिजर में रख दिया। मैं चकित हूं कि अपने प्रेम को जीवित रखने के लिए लोग क्या-क्या करते हैं।'

*© The New York Times 2023*

## आंकड़े

### समय पर उड़ान

घरेलू एअरलाइंस में समय पर उड़ान भरने के मामले में इंडिगो शीर्ष पर है। उसके बाद स्पाइसजेट व एअर इंडिया का स्थान है।

| एअरलाइन | समय पर उड़ान |
|---|---|
| इंडिगो | 93.9% |
| स्पाइसजेट | 92.4% |
| एअर इंडिया | 88% |
| गो फर्स्ट | 83% |
| विस्तारा | 73.8% |

नोट : आंकड़े 19 जनवरी, 2023 तक के हैं। | स्रोत : MoCA

संत लूथर ने कहा-'हमें अपने मन, वाणी व विचारों पर संयम रखना आवश्यक है। हमें ऐसी बाधाओं से पथभ्रष्ट होने की आवश्यकता नहीं है।'

## मन, वाणी व विचारों पर संयम

अंतर्यात्रा | संकलित

**संत** मार्टिन लूथर एक प्रसिद्ध समाजसेवक थे। वह समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाकर लोगों को समाज सुधार की प्रेरणा देते थे। उनके ऐसा करने से कुरीतियों को बढ़ावा देने वाला और दुर्जनों को पोषण देने वाला वर्ग उनसे क्रुद्ध रहता था।

एक बार ऐसे ही एक समुदाय ने संत लूथर के समाज सुधार के कार्यों से बौखलाकर उनके एवं उनके शिष्यों के विरुद्ध अभियान-सा छेड़ दिया। वे लोग जब भी संत मार्टिन लूथर या उनके शिष्यों को देखते, तो अकारण ही उन्हें गालियां देते, उन पर फब्तियां कसते, यहां तक कि उन पर पत्थर भी फेंकने लगते। उन दुराचारियों के उत्पीड़न से तंग आकर कुछ शिष्यों ने संत मार्टिन लूथर से कहा–'लगता है कि हमें भी इनकी गालियों का उत्तर गालियों से देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, ताकि इन्हें सबक सिखाया जा सके।' संत लूथर उन्हें रोकते हुए बोले–'ऐसा करने पर हममें और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? यदि हम भी उनकी तरह करने लगे, तो अपने महान उद्देश्य से भटक नहीं जाएंगे? हमें अपने मन, वाणी व विचारों पर संयम रखना आवश्यक है। समाज सुधार के कार्य में ऐसी बाधाएं तो आती हैं, उनसे विचलित होकर हमें स्वयं पथभ्रष्ट होने की आवश्यकता नहीं है।' यह सुनकर उनके शिष्य शांत हो गए।

*(अमर उजाला आर्काइव से)*

## अमर उजाला पुराने पन्नों से — 5 अक्तूबर, 1994

### पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 30 की गई जान



झांसी में पटाखा फै[...] में विस्फोट : ३० म[...]

अमर उजाला ब्यूरो

(शेष पृष्ठ तीन पर)

**झांसी कोतवाली थाना क्षेत्र में पटाखा बनाने के कारखाने में विस्फोट हो जाने से उसमें काम करने वाले 30 मजदूरों की मौत हो गई और अन्य तीस घायल हो गए। मरने वालों में ज्यादातर नाबालिग बच्चे हैं।**

# युवा आबादी है देश का लाभांश

**भारत को विकसित देश बनाने के लिए जरूरी है प्रति व्यक्ति औसत आय बढ़े और इसमें युवा अहम भूमिका निभा सकते हैं।**



प्रहलाद सबनानी | अर्थव्यवस्था

पूरे विश्व में सभी देशों का सकल घरेलू उत्पाद कुल मिलाकर लगभग 100 लाख करोड़ डॉलर है। इसमें भारत का हिस्सा मात्र 3.50 प्रतिशत है, अर्थात भारत का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 3.50 लाख करोड़ डॉलर है। जबकि, पूरे विश्व के 17.5 प्रतिशत से अधिक लोग भारत में निवास करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से तुलना की जाए, तो भारत का सकल घरेलू उत्पाद बहुत कम है, जिसे केंद्र सरकार एवं कई राज्य सरकारें मिलकर अब बहुत आगे ले जाने के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करती दिखाई दे रही हैं। हालांकि, पूरे विश्व में सकल घरेलू उत्पाद के मामले में भारत पांचवें स्थान पर आ गया है और अब उससे आगे केवल अमेरिका, चीन, जापान एवं जर्मनी जैसे देश हैं। परंतु, अधिक जनसंख्या होने के कारण भारत में प्रति व्यक्ति आय अन्य कई देशों की तुलना में बहुत कम है। प्रत्येक भारतीय की औसत आय 2,200 डॉलर प्रति वर्ष है, जबकि अमेरिका में



प्रति व्यक्ति औसत आय 70,000 डॉलर प्रति वर्ष है और चीन की जनसंख्या भारत से भी अधिक होने के बावजूद प्रत्येक चीनी नागरिक की औसत आय 12,000 डॉलर प्रति वर्ष है। इस प्रकार देश में प्रति व्यक्ति औसत आय बढ़ाने का प्रयास किया जाना अब बहुत जरूरी है, जिसमें भारत की युवा शक्ति को अपना योगदान देना आवश्यक हो गया है। आज किसी भी देश के लिए जनसंख्या का अधिक होना और उसमें भी युवा जनसंख्या की भागीदारी ज्यादा होना, उस देश के लिए बहुत लाभकारी स्थिति बन जाती है। वह भी तब, जब विशेष रूप से कई विकसित देशों यथा, जापान, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कनाडा आदि में जन्म दर बहुत कम हो चुकी हो एवं इन देशों में प्रौढ़ नागरिकों की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही हो एवं युवा जनसंख्या का अभाव महसूस किया जा रहा हो। इस प्रकार भारत युवा जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ही लाभप्रद स्थिति में आ गया है। भारत की कुल 140 करोड़ जनसंख्या में से 50 प्रतिशत जनसंख्या की आयु 25 वर्ष से कम है और 65 प्रतिशत जनसंख्या की आयु 35 वर्ष से कम है। सबसे अधिक युवा, अर्थात 18-35 वर्ष के आयु वर्ग में 60 करोड़ भारतीय नागरिक आते हैं। भारतीयों की औसत आयु मात्र 29 वर्ष है, जबकि चीन के नागरिकों की औसत आयु 37 वर्ष एवं जापान के नागरिकों की औसत आयु 48 वर्ष है। इसीलिए भारत को एक युवा देश कहा जा रहा है और पूरे विश्व की निगाहें आज इस पर टिकी हुई हैं। अब तो यह स्थिति दिखाई देने लगी है कि यदि भारत आर्थिक प्रगति करेगा, तो पूरा विश्व ही आर्थिक प्रगति करता हुआ दिखाई देगा।

आज भारत में साक्षरता दर 80 प्रतिशत के आसपास पहुंच गई है, जो कि एक बहुत अच्छी दर कही जा सकती है। हालांकि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में शिक्षा का स्तर अलग-अलग दिखाई देता है। इसलिए, भारत के युवाओं में कौशल के अभाव में देश के आर्थिक विकास में इनका योगदान संतोषप्रद स्तर तक नहीं हो पा रहा है। कौशल के अभाव में इस वर्ग की उत्पादकता भी तुलनात्मक रूप से कम दिखाई देती है। भारत के युवाओं में शिक्षा के स्तर को और अधिक सुधारने के लिए हाल ही में भारत में कई नए उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। भारत में शिक्षित युवा कई विकसित देशों में पहुंचकर वहां के प्रौद्योगिकी, मेडिकल एवं प्रबंध के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं एवं इन देशों के कई निजी संस्थानों को तो एक तरह से भारतीय ही चला रहे हैं। आज खाड़ी के कई देशों के साथ ही जापान के अस्पतालों तक में भारतीय नर्सों की बहुत अधिक मांग है। केंद्र सरकार की नीतियों के चलते ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी और खाड़ी के देश आज भारतीय मूल के नागरिकों पर विश्वास करते हुए उन्हें राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आदि क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं।

आज आवश्यकता इस बात की है कि देश के युवाओं को आगे आकर केंद्र और राज्यों की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर अपने कौशल को विकसित कर देश के विकास में अपने योगदान को बढ़ाना चाहिए, ताकि भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाया जा सके।